बेका पर समझौता हो गया

इससे पहले दोनों देश 2002 में जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इनफॉर्मेशन एग्रीमेंट, 2016 में लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरैंडम ऑफ एग्रीमेंट और 2018 में कॉम्पैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट पर दस्तखत कर चुके हैं।

मनोज शाह।।

आखिरकार भारत और अमेरिका के बीच उस बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट (बेका) पर समझौता हो गया जिस पर बरसों से काम चल रहा था। यह दोनों देशों के बीच सामरिक सहयोग बढ़ाने की समझ के तहत किया जाने वाला चौथा समझौता है। इससे पहले दोनों देश 2002 में जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इनफॉर्मेशन एग्रीमेंट, 2016 में लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरैंडम ऑफ एग्रीमेंट और 2018 में कॉम्पैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट पर दस्तखत कर चुके हैं। माना जा रहा है कि बेका समझौता दोनों देशों के बीच रक्षा और भू–राजनीति के क्षेत्र में सहयोग और तालमेल को पूर्णता प्रदान करने वाला है। हालांकि अमेरिका जैसी सुपरपावर के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने की बात जब भी उठती है तब उसके साथ कई तरह की आशंकाएं भी जुड़ी होती हैं। इसी बेका समझौते को लेकर जब बातचीत शुरू हुई तो तत्कालीन यूपीए सरकार ने कई तरह की चिंताएं जाहिर की थीं। समझौते के इस बिंदु तक पहुंचने में अगर इतना वक्त लगा तो उसका कारण यह था कि लंबी बातचीत के जरिए दोनों पक्षों ने एक–दूसरे की आशंकाओं को दूर करने के रास्ते खोजे और फिर सहमति को पक्का किया।

सबसे अधिक मनोरंजन करने वाला ऐप! साइप–अप करने पर पाएं 500 रुपए

बहरहाल, इस समझौते के बाद अब भारत को अमेरिकी सैन्य उपग्रहों द्वारा जुटाई जानी वाली संवेदनशील सूचनाएं और चित्र रियल टाइम बेसिस पर उपलब्ध हो सकेंगे। अमेरिका वैसे महत्वपूर्ण आंकड़े, मैप आदि भी भारत के साथ शेयर कर सकेगा जिनके आधार पर अपने सामरिक लक्ष्य पूरी सटीकता से हासिल करना भारत के लिए आसान हो जाएगा। खासकर दो पड़ोसी राष्ट्रों के साथ मौजूदा तनावपूर्ण रिश्तों के संदर्भ में देखें तो यह समझौता विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन ऐसे समझौते तात्कालिक संदर्भों तक सीमित नहीं होते। न ही ये एकतरफा तौर पर फायदेमंद होते हैं। ध्यान रहे, यह समझौता ऐसे समय हुआ है जब अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव अपने अंतिम दौर में है। दो देशों के बीच कोई समझौता यूं भी किसी खास सरकार का मामला नहीं होता, लेकिन अमेरिकी आम चुनाव की मतदान तिथि से ऐन पहले हुआ यह समझौता इस बात को भी रेखांकित करता है कि दोनों देशों के संबंध अब खास नेताओं के बीच की पर्सनल केमिस्ट्री पर निर्भर नहीं रह गए हैं। यह दोनों देशों के बीच बढ़ते सहयोग और बेहतर होते तालमेल का ठोस संकेत है। किसी भी अन्य रिश्ते की तरह यह नजदीकी भी दोनों देशों को लाभ पहुंचा रही है। सिर्फ रक्षा क्षेत्र की बात करें तो भारत–अमेरिका सहयोग बढ़ना शुरू होने के बाद से, यानी 2007 से अब तक अमेरिकी कंपनियां भारत को 21 अरब डॉलर से ज्यादा के हथियार बेच चुकी हैं। बदली परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए दोनों देशों के रिश्तों में बढ़ता तालमेल न केवल भारत और अमेरिका के राष्ट्रीय हितों की दृष्टि से बल्कि विश्व शांति और क्षेत्रीय संतुलन के लिए भी उपयोगी है।

संदेह

अशोक वोहरा।

धर्म-दर्शन

एक बात आप निश्चित रूप से समझ लें कि महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित मूल रामायण में केवल ६ कांड ही थे – बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड एवं युद्ध कांड। लंका कांड में श्रीराम के राज्याभिषेक के साथ ही महर्षि वाल्मीकि ने रामायण का समापन कर दिया। वाल्मीकि रामायण के इन ६ कांडों की विशेषता ये है कि महर्षि वाल्मीकि ने इसे घटनाओं के घटित होने से पूर्व ही लिख दिया था क्यूंकि ब्रह्मदेव के वरदान से वे त्रिकालदर्शी थे। साथ ही साथ इन सभी ६ कांडों में स्वयं महर्षि वाल्मीकि की स्थिति गौण है। तत्पश्चात युद्ध के समय जब गरुड़ को श्रीराम के विष्णु अवतार होने पर संदेह हो गया तो महादेव के कहने पर काकभुशुण्डि ने उनका संदेह दूर किया जो स्वयं ११ बार रामायण और १६ बार महाभारत होते देख चुके थे।

संपादकीय

मजबूत होती जाति

जातिवादी राजनीति का ही परिणाम है कि किसी एक जाति को आधार बना कर चलने वाली पार्टियां आज नीतीश–मोदी के साथ तो अगली सुबह तेजस्वी–राहुल के साथ दिखाई दे रही हैं। अगर दोनों खेमों में से किसी के पास जगह नहीं मिली तो वे अकेली ही खड़ी हो गईं। राजनीति को विचारविहीन, अवसरवादी तथा जातिवादी बनाने का उन्होंने प्रण ले रखा है। कायदे से मुजफ्फपुर शेल्टर होम कांड और हाथरस कांड जैसे औरतों पर अत्याचार के मामले चुनाव में बड़ा मुद्दा बनने चाहिए थे। लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं देता। राजनीति में विचारधाराओं की भूमिका नगण्य हो चुकी है। सांप्रदायिकता, जातिवाद, उपभोग और गैर–बराबरी की विचारधारा ने राजनीति को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। बिहार समाजवाद, सर्वोदय, नक्सलवाद से लेकर संसदीय वामपंथ और सामाजिक न्याय तक तमाम विचारधाराओं की प्रयोगशाला रहा है। यहां गांधी, लोहिया तथा जयप्रकाश से लेकर चारु मजूमदार तक के अनुयायी मिलते हैं। सीपीआई और सोशलिस्ट पार्टी ने किसानों के बड़े आंदोलन चलाए। लेकिन न भूमि की समस्या का कोई हल निकला और न ही जाति की समस्या का। बल्कि जाति तो मजबूत ही होती जा रही है। डॉ. राममनोहर लोहिया तथा डॉ. बाबा साहेब आंबेडकर के मानने वालों ने जातियों की गोलबंदी को ही अपना लक्ष्य बना लिया है। हर जाति का संपन्न और पढ़ा–लिखा तबका जाति के नाम पर सत्ता में अपना हिस्सा मांग रहा है। वह सत्ता पाने के लिए कथित उच्च जातियों वाले तरीके ही अपनाता है। सीपीआई–एमएल और जेपी के अनुयायियों की पार्टी न्यू भारत मिशन में बदलाव की ललक जरूर दिखाई देती है, लेकिन यह हाशिए की बात है। इस तर के चुनाव से लोकतंत्र भला कितना संपन्न होगा?

सरकार ने बात नहीं सुनी और चुनाव आयोग ने भी ध्यान नहीं दिया। चुनाव जैसा गतिशील और उत्तेजना से भरा कार्यक्रम एक दबे-दबे माहौल में नहीं होना चाहिए था।

आकाश से उतरते प्रत्याशी

अनिल सिन्हा।।

किसी लोकतंत्र में चुनाव आम तौर पर नई फसल की तरह नई राजनीति के बीज लेकर आते हैं लेकिन भारत में होने वाले चुनाव लोकतंत्र की बेहतरी की उम्मीद नहीं जगा पाते। चुनाव हो जाने के बाद पता चलता है कि वे लोकतंत्र को जरा भी समृद्ध नहीं कर पाए। क्या बिहार जैसे बड़े और संपन्न राजनीतिक अतीत वाले राज्य के चुनावों में इस बार कुछ अलग होगा? राज्य में इस बार चुनावी प्रक्रिया की शुरुआत कुछ इस तरह हुई है कि लोगों का उत्साह ठंडा ही रहने वाला है। विपक्षी पार्टियों तथा जनता के बड़े हिस्से को कोरोना महामारी में चुनाव कराना सही नहीं लग रहा था। लेकिन सरकार ने बात नहीं सुनी और चुनाव आयोग ने भी ध्यान नहीं दिया। चुनाव जैसा गतिशील और उत्तेजना से भरा कार्यक्रम एक दबे–दबे माहौल में नहीं होना चाहिए था।

क्या सामान्य माहौल होता तो लोकतंत्र को समृद्ध करने में कोई मदद मिलती? इसका उत्तर भी नकारात्मक ही है। देश की राजनीति में जो एक तरह का ठहराव आ गया है, वह बिहार जैसे राज्य में ज्यादा साफ दिखता है। राजनीति में सतही तौर पर नजर आने वाली अच्छाई भी इस राज्य में नहीं है। पार्टियों के भीतर आंतरिक

लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं बची है। इस मायने में वामपंथी दलों की हालत अभी भी काफी बेहतर है। उनके यहां उम्मीदवारों के चयन में पार्टी की स्थानीय यूनिट की बात का अधिक महत्व होता है। बाकी पार्टियों में स्थानीय यूनिट का कोई मतलब नहीं है। आरजेडी, जेडीयू जैसी पार्टियां तो एक ही व्यक्ति के नेतृत्व में चलती हैं। इसलिए उम्मीदवारी पाना भगवान से मिले वरदान की तरह है। ऐसे में आकाश से उतरने वालों की संख्या ही ज्यादा होती है।

वही किस्से इस बार भी सुनाई दे रहे हैं कि जमीन पर संघर्ष करने वालों को नजरअंदाज किया गया और एक दिन पहले पार्टी में शामिल होने वालों को टिकट मिल गया। टिकट बिकने–खरीदने की शिकायत आम है। यही कारण है कि कार्यकर्ता जमीन पर संघर्ष करना छोड़ चुके हैं। वे पटना और दिल्ली में बैठे नेताओं के यहां चक्कर लगाते रहते हैं। टिकट बंटवारा ही बता देता है कि बाहुबल तथा धनबल का कितना जोर रहेगा। वैसे बिहार के मौजूदा चुनावों को देश की राजनीति पर बड़ा असर डालने वाला चुनाव बनाना मुश्किल नहीं था। यह काम अकेले प्रवासी मजदूरों की बेचारगी की अवस्था में गांव वापसी के मुद्दे के जरिए ही हो सकता था। इस घटना ने एक राज्य नहीं, पूरे देश की अर्थव्यवस्था और समाज–व्यवस्था को उघाड़ कर रख दिया है।

पलायन अंग्रेजों के शासन की देन है। उसके पहले अकाल, महामारी, युद्ध और बेहतर अवसर ही पलायन के कारण थे। जीवन चलाने के लिए नियमित पलायन औपनिवेशिक शासन का परिणाम है क्योंकि अंग्रेजों ने सारे परंपरागत रोजगार खत्म कर दिए और सिर्फ खेती से सारे लोगों का जीवन नहीं चल सकता था। आजादी के आंदोलन में भारत को उद्योगविहीन करने का किस्सा रोज की चर्चा का विषय था। लेकिन आजादी के बाद इस पर चर्चा करीब–करीब बंद हो गई और गांव के रोजगारों को खत्म करने का सिलसिला जारी रहा।

सूडोकु नवताल- 5519

मध्यम

4			9		6	1		8
6	8							
	1	7	3	8		4		
3	4		6		7			9
5		1	8			2		7
2			5		1		8	4
		3		7	5	8	6	
							9	5
7		6	2		8			1

Jagrutidaan.com, Bangalore

■ प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं.
■ प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3×3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें.
■ पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते.
■ पहेली का केवल एक ही हल है.

सूडोकु नवताल -5518 का हल

2	9	8	3	5	6	1	7	4
4	5	3	2	1	7	9	8	6
7	1	6	4	8	9	2	5	3
8	2	5	6	9	1	3	4	7
3	6	4	7	2	5	8	1	9
1	7	9	8	3	4	5	6	2
5	4	1	9	7	2	6	3	8
6	3	2	1	4	8	7	9	5
9	8	7	5	6	3	4	2	1

अपना ब्लॉग

भ्रम पैदा करने की कोशिश

मोहन। गांधी जी की मौत के साथ ही गांवों में रोजगार मुहैया कराने का मुद्दा कांग्रेस के राजनीतिक कार्यक्रम से हट गया था। बाद में, नब्बे के दशक में स्वदेशी वगैरह का नाम देकर आरएसएस से जुड़े स्वदेशी जागरण मंच जैसे संगठनों ने भ्रम पैदा करने की कोशिश जरूर की। इसी दौरान खादी जैसे खांटी स्वदेशी कार्यक्रम को कॉरपोरेट ब्रैंड में बदला गया। बिहार जैसे राज्य से पलायन रोकने के लिए गांधी जी वाली स्वदेशी नीति चाहिए। इसके लिए बिहार की कोई पार्टी तैयार नहीं है। राज्य में वही पुरानी बहस चल रही है कि कारखाने क्यों नहीं लगे। उन्हें कौन बताए कि औद्योगिक रूप से विकसित राज्यों में भी किसान आत्महत्या कर रहे हैं और गांव से शहर की ओर बड़े पैमाने पर पलायन हो रहा है। महाराष्ट्र और गुजरात के सबसे शक्ति–संपन्न तबके मराठा और पटेल आरक्षण मांग रहे हैं।